खुद गन्दगी में रहो और भारत को स्वच्छ बनाओ!

ग्राउंड ज़ीरो से विवेक की रिपोर्ट

स्वच्छ भारत अभियान के नाम पर झकाझक सफेद कपड़ों में चमचमाते झाड़ू लेकर फोटो खिंचाते नेताओं की तस्वीर हम सभी ने बहुत देख लीं। अमिताभ बच्चन की मीठी बनावटी फटकार भी विज्ञापनों में बहुत देख लीं। सवाल है, हम अपने सफाई कर्मी को कितना जानते हैं?

2014 से भारत में सफाई का फैशन विकराल रूप लेता जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान की शक्ल में गाँधी जी के सपने को जीने का संकल्प लेकर प्रधान मंत्री मोदी ने बिना सामाजिक व्यवस्था को बदले कॉर्पोरेट यारों पर सरकारी खजाना लुटा देश को चमकाने का बीड़ा उठाया है। पर जिनके कन्धों पर इस अभियान का जिम्मा है उनकी दशा जाननी उतनी ही जरूरी है जितना सरहद के सिपाही की।

स्वच्छता टैक्स मोदी को दो और सफाई खुद करो

मुकेशी देवी सेक्टर 9 फरीदाबाद में 500 गज के पाँच घरों में साफ सफाई का काम करती हैं और तीन घरों में बर्तन भी साफ करती हैं। 42 वर्ष की उम्र में 55 की दिखने वाली मुकेशी को एक घर की सफाई में लगभग एक घंटा लगता है। सुबह । बजे बाईपास स्थित अपने कमरे से निकल दोपहर 2 बजे ही वापस पहुँच पाती हैं।

एक घर को छोड़ बाकी सभी मानो मेरे खून के प्यासे हैं, ये कहते हुए मुकेशी हँस पड़ी। काम लेते समय तय राशि के साथ काम भी तय हो जाता है पर जैसे ही कुछ रोज निकलते हैं तय किये हुए काम से अलग दूसरे कई काम भी सर पर आने शुरू हो जाते हैं, बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के।

22 वर्षीया दीपा हरदोई उत्तरप्रदेश से पहले दिल्ली आई और अब फरीदाबाद में बर्तन, झाड़ू, करने का काम करती हैं। बीते दिनों उसे तेज बुखार ने जकड़ लिया फिर भी उसकी मां ने काम पर आना बंद नहीं करवाया। एक दिन बुखार अपने प्रचंड रूप में आ गया तो दीपा काम पर नहीं जा सकी। एक महीने में दो छुट्टी का भुगतान दीपा ने काम से हाथ धो कर चुकाया। इन बड़े मकानों में रहने वाले खुद यूरोप और अमेरिका की सैर को गाहे बगाहे जाते रहते हैं पर कामगारों की छुट्टी कामचोरी में गिनते हैं।

रेणु स्कूल जाने की उम्र में पोछा लगाने का हुनर सीख रही है। दीपा की ही तरह रेणु का दो दिन काम पर न जाना उसके गले की फांस बन गया। रेणु की मां ने बताया कि अगर एक दो छुट्टी कर लो तो मालिक अन्य किसी को काम पर रख लेते हैं। बीमार होने की सूरत में भी छुट्टी लेना मोहाल है क्योंकि काम छूट जाने के सूरतेहाल आर्थिक समस्या से जूझता परिवार और परेशान हो जाता है। कहीं स्कूल की फीस रुकती है तो कहीं इलाज।

55 वर्षीय टेकचंद साइकिल रिक्शा से घर घर का कचरा उठाते हैं। जबसे इकोग्रीन कंपनी को निगम ने ठेका दिया है इनका काम मंदा होता जा रहा है। टेकचंद का मानना है कि कम्पनी द्वारा कूड़ा उठवाया जाना बेहतर हो सकता है क्योंकि वो इस काम को संगठित और व्यवस्थित रूप से करते हैं परन्तु, इसके बदले में टेकचंद जैसों को रोजगार का दूसरा विकल्प भी तो मिले। जाति विशेष से आने के कारण घर में काम देने को कोई राजी नहीं होता और चौकीदारी जैसा रात को जागने का काम अब इस उम्र में कर नहीं सकते। सो भूखों मरने की नौबत आ सकती है।

भगवान् स्वरूप योगी आदित्यनाथ की नगरी गोरखपुर की रहने वाली 80 वर्षीय भोनिया की व्यथा सुन कर स्वयं भगवान् के रोंगटे खड़े हो जाएं। भोनिया इस उम्र में पहले अपने गाँव के उच्च वर्गीय भूमिहार परिवारों के घर द्वार की सफाई करती थीं। एक दो लोगों को छोड़ कर कोई भी दूसरा भूमिहार किसी प्रकार का भुगतान नहीं करता और जो करता है वो भी मात्र 100 रूपए। इसका मुख्य कारण ये है कि सवर्ण समाज का अधिकांश हिस्सा मानता है कि दलित व्यक्ति भूमिहार के घर काम करे इसी के लिए उसका जन्म हुआ है। इसी बीच फ़रीदाबाद में उनके एकमात्र बेटे के निधन की खबर ने भोनिया का संसार ही समाप्त कर दिया। बेटे की लाश लेने आई भोनिया गाँव वापस जाने तक के पैसे नहीं जुटा पाई।

अपने 6 वर्षीय पोते के उज्जवल भविष्य की आस लगाये भोनिया सेक्टर 15 फरीदाबाद के बाजार में एक रेहड़ी वाले के जूठे बर्तन धोती है और तड़के कुछ दुकानदारों की दुकान साफ करती है। कुल मिलाकर महीने में सिर्फ 4000 रुपये जुटा पाने वाली भोनिया गरीबों की शरणस्थली बाईपास पर झुग्गी डालकर जीवन के अंतिम दिनों की बाट जोह रही है।

योगी और खट्टर जैसों से इन दबे कुचलों को उबारने की आस लगाना वैसा ही है जैसा नरभक्षी से जीवनदान की आस। पूंजीवादी लोकतंत्र में इन गरीबों की जरूरत मोदियों को सिर्फ वोट देने और रैलियों में पार्टियों के झंडे उठा कर चलने तक ही है। इस देश में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है ये कहते हुए कि उसने सड़क पर चाय बेची, उसकी माँ ने बर्तन धोये और आज भोनिया में उसे अपनी मां नहीं दिखती। आज वह इस वर्ग के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सब कुछ कर सकता है लेकिन सिर्फ नए कपड़े पहन कर कलश यात्रा कर रहा है।

समाज में इन सफाई कर्मियों की आवश्यकता कितनी है ये तब समझ आती है जब निगमकर्मी हड़ताल पर हों या हमारे घर में सफाई करने वाला कार्मिक कुछ रोज न आये। फरीदाबाद का बाईपास इनकी झुगियों से पटा पड़ा है। हमारे घरों को चमकाने का जिम्मा उठाने वाली इन कर्मियों का जीवन नरक है।

श्रमिकों के लिए साप्ताहिक अवकाश की अवधारणा सर छोटूराम के अथक प्रयासों से परतंत्र भारत में लागू हुयी। पर आज के काले अंगरेजों के शासन वाले भारत में इन गरीबों को एक दिन का आराम मयस्सर नहीं।

कहने को सरकारी नीतियों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रावधानों की कमी नहीं। लेकिन हमारे और आपके घरों को चमकाये रखने वाले खुद कितनी गन्दगी और बदबूदार जगह पर जीवन भर रहते हैं इसका अंदाजा किसको है? प्रधानमन्त्री मोदी की सबको घर देने की योजना में इनके लिए भी साफ घर और परिवेश शामिल है या नहीं?

शराब के ठेके के खिलाफ़ जनता की मुहिम रंग लाई
मज़दूर मोर्चा की रिपोर्ट पर सरकार जागी
कैसी विधायक हैं सीमा त्रिखा, जिन्होंने दस सोसाइटी की महिलाओं का दर्द न समझा

मज़दूर मोर्चा ब्यूरो

फरीदाबाद: फरीदाबाद: सेक्टर 48 गीता निवास के सामने से शराब का ठेका हटाने की मुहिम की बहुत बड़ी जीत हुई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा) के अधिकारी यहाँ शुक्रवार शाम को पहुँचे। उन्होंने ठेके के बग़ल में अवैध रूप से चलाए जा रहे अहाते को बंद कर दिया। इसके अलावा ठेके वाले को आदेश दिया कि वह ठेके का मुँह गीता निवास सेक्टर 48 की तरफ़ से मोड़कर उल्टी दिशा में कर देगा। वहाँ एक बड़ी चादर लगाकर उसे ढक दिया जाएगा ताकि कुछ दिख न सके। इसके अलावा वहाँ खड़ी जेसीबी और ट्रकों को भी हटाया जाएगा। वहाँ लगने वाले बुध बाज़ार से कोई रंगदारी वसूलने प्रशासन का कर्मचारी नहीं आएगा।

शराब ठेका हटाने की मुहिम का संचालन करने वाली सोशल वर्कर परमीता चौधरी और बाबा रामकेवल अनशनधारी ने बताया कि यह कार्रवाई मज़दूर मोर्चा के पिछले अंक में प्रकाशित रिपोर्ट पर हुई है। सरकार के पास चंडीगढ़ में मज़दूर मोर्चा के रिपोर्ट की कॉपी पहुँची, फिर वहाँ से सरकार ने कार्रवाई का आदेश दिया।

परमीता चौधरी और बाबा का कहना है कि हमने ठेके वालों को सामान हटाने और बाकी सारी कार्रवाई के लिए एक सप्ताह का समय दिया है अगर इस दौरान सारी कार्रवाई संपन्न नहीं होती है तो हमारा आंदोलन फिर से शुरू हो जाएगा।

फरीदाबाद के सेक्टर 48 में शराब का ठेका हटाने की मुहिम छेड़ने में महिलाओं की एकजुटता ही काम आई। लेकिन उस इलाके के पुरुष ज्यादा तादाद में उनका समर्थन करने की बजाय घरों में चूड़ियां पहन कर बैठे रहे। महिलाओं ने शराब का ठेका हटवाने के लिए वहां दिन रात धरना-प्रदर्शन करके प्रशासन को झुकने को मजबूर किया।

सेक्टर 48 में गीता सोसायटी के सामने बने ठेके को हटवाने के लिए यहां की दस सोसायटी की महिलाएं एकजुट होकर पिछले 15 दिनों से आंदोलन चला रही थीं। इस हफ्ते उनका आंदोलन तब उग्र हो गया जब बड़खल विधानसभा क्षेत्र की भाजपा विधायक सीमा त्रिखा ने इन लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया और फिर बेइज्जती कर दी।

इस घटनाक्रम से महिलाएं इतनी आहत हुईं कि इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता परमीता चौधरी के नेतृत्व में अपने आंदोलन को तेज करने का फैसला किया। महिलाओं ने घोषणा की है कि अब वह लोग यहां रात को भी शराब के ठेके के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगी। परमीता चौधरी ने गुस्से में कहा कि सीमा त्रिखा आखिर कैसी महिला हैं जिन्होंने हम महिलाओं का दर्द नहीं समझा और इस ठेके को यहां से हटवाने में दिलचस्पी नहीं ली। यहां की प्रदर्शनकारी महिला कलावती ने सवाल उठाया कि क्या सीमा त्रिखा को इस ठेके से हर महीने कुछ पैसा मिलता है जो ठेका हटवाने में रूचि नहीं ले रही थीं। कलावती का कहना था कि अगर सीमा त्रिखा यह ठेका नहीं हटवा पा रही थीं तो कम से कम हमारे बीच आकर यह कह तो सकती थीं कि वह हमारे साथ हैं, बेशक उनसे यह ठेका नहीं हट पा रहा है।

हालांकि परमीता चौधरी का कुछ और ही कहना है, वह कहती हैं कि इस आंदोलन से भाजपा नेता घबरा गए। वह अगर समर्थन करते और यह ठेका हट जाता तो इसका श्रेय हमारे आंदोलन को मिलता। इसलिए भाजपा किसी और संगठन को इसका लाभ भी नहीं लेने देना चाहती थी। यही हाल सीमा त्रिखा का भी है, वह जानबूझकर आंखें बंद रखे हुए थीं, वह नहीं चाहतीं कि बिना उनकी मदद कोई आंदोलन कैसे सफल हो जाएगा।

बहरहाल, इस इलाके की महिलाओं में आंदोलन को लेकर जबरदस्त उत्साह है। यहां पर धरना प्रदर्शन करना कम जोखिम का काम नहीं है। ज्यादातर ठेकों पर रौनक हर वक्त होती है। महिलाओं के लगातार धरना देने पर यहां कानून व्यवस्था बिगड़ सकती थी। हालाँकि यहाँ के लोगों की यह जीत अधूरी है। अभी उन्हें तमाम समस्याओं के लिए जूझना होगा। बहरहाल, मज़दूर मोर्चा उनकी हर मुहिम में साथ है।

पिछली सरकार ने उजाड़ा....

पेज एक का शेष

बेशक गूजर जी इस राजमार्ग पर कई बार नारियल फ़ोड़ चुके हैं परन्तु काम अभी अधूरे पड़े हैं। पैदल यात्रियों के लिये सड़क पार करने के लिये न तो आवश्यक पुल बनाये गये और न ही दुर्घटनायें रोकने के लिये ग्रिल लगाई गयीं। इसके चलते औसतन एक राहगीर की मौत रोज़ाना इस सड़क पर हो रही है। इसके अलावा, एक-दो पुलों को छोड़ कर बाकियों पर रोशनी की व्यवस्था न होने से भी कई दुर्घटनाये हो चुकी है। मुख्य सड़क पर चढने व उतरने के लिये व्यवस्थायें अभी की जा रही हैं। जो ग्रिलें लगाई जा रही हैं वे केवल खानापूर्ति के लिये ही प्रतीत हो रही हैं।

मैट्रो रेल सेवा का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी से बेशक करा लिया हो परंतु उसके बनने में इनका कोई योगदान नहीं है। अपनी उपलब्धियों में केजीपी (कुंडली गाजियाबाद पलवल) व केएमपी (कुंडली मानेसर पलवल) मार्ग को गिनाना भी गूजर जी नहीं भूलते। जबकि इन दोनों ही प्रोजेक्टों का कार्य 2004 में शुरू हो चुका था। उसके बावजूद 4 साल में मोदी सरकार केवल केजीपी ही पूरा करा पाई है केएमपी अभी बाकी है। जानलेवा बने 135 किलोमीटर लम्बे मार्ग पर टोल टैक्स इतना भारी भरकम कि इसकी पूरी लागत एक से दो वर्ष में निकाल ली जायेगी। उसके बाद सारी उम्र लूट कमाई का धंधा चलता रहेगा। फ़रीदाबाद को केजीपी से जोड़ने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। गांव चंदावली से मौजपुर के रास्ते वहां पहुंचने वाली सड़क इतनी संकरी है कि भारी वाहनों के चलते जाम लग जाता है।

रेल यात्रियों की दुर्दशा

प्रतिदिन पलवल से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की संख्या 50 000 से ऊपर है। कोसी व मथुरा तक से जो आते हैं वे अलग। ट्रेनों व उनमें लगे कोचों की संख्या कम होने के चलते यात्री इनमें भूसे की तरह ठुसे रहते हैं। एक-एक कोच में 100 की जगह 300 यात्री ठुंसने को मजबूर रहते हैं। इतना ही नहीं रेलवे का जब दिल करता है इन ट्रेनों की संख्या घटा देती है। सर्दियों में एक दिन धुंध पड़ जाये तो महीनों शटल बन्द हो जाते हैं। एक दिन यमुना का जल स्तर बढ जाय तो हफ़्तो तक कई शटल बंद रहते हैं। कभी सिग्नल, कभी लॉकिंग। इन्टरलॉकिंग व पटरियों की मुरम्मत के नाम पर भी प्राय: शटल ही बंद किये जाते हैं। जबकि इनके यात्री अग्रिम भाड़ा दे चुके होते हैं। इसका कोई रिफ़ंड भी नहीं होता।

झूठ बोलने में मोदी सरकार के अफ़सर भी पीछे नहीं रहना चाहते। इन्हीं दिनों फ़रीदाबाद बल्लबगढ स्टेशनों के दौरे पर दिल्ली मुख्यालय से आये एक बड़े रेलवे अधिकारी आरएन सिंह ने कहा कि कई वर्षों से अधूरी पड़ी चौथी लाइन इसी दिसम्बर में व फ़रीदाबाद स्टेशन की नई इमारत मार्च 2019 तक पूरी हो जायेगी। लेकिन वास्तव में मोदी सरकार के पांच साल पूरे होने तक के समय में इन कामों का सम्पन्न होना दिखाई नहीं देता।

ट्रेनों की संख्या बढाने से साफ़ इन्कार करते हुये सिंह साहब ने कहा कि कुछ ट्रेनों में कोचों की संख्या बढाने पर विचार किया जा सकता है। यानी मौजूदा 10-10 कोचों वाले शटलों में कोच बढाने में भी कृष्णपाल की सरकार पर जोर पड़ रहा है। अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चला सकते तो मौजूदा 10-10 कोचों वाली ट्रनों में 10-10 कोच और जोड़ दिये जायें तो यात्री कम से कम इन्सानों की तरह तो यात्रा कर लेंगे। लेकिन स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री गूजर को नारियल फ़ोड़ने से फ़ुर्सत मिले तब तो वे यह सब सोचें। संदर्भवश, यहां गौरतलब है 2015-16 के रेल बजट में जब मंथली पास के दाम बढाये गये थे तो मुंबई के सांसद इसके विरोध में अड़ गये थे। इस पर रेलवे ने वहां के दाम नहीं बढाये। लेकिन फ़रीदाबाद का सांसद सोया रहा और यहां के दाम बढा दिये गये।

इसी तरह शिक्षा, चिकित्सा व औद्योगिक क्षेत्र में गूजर की भाजपा सरकार ने कौन से तीर मारे हैं वे जनता के सामने हैं। शिक्षा के नाम पर फ़र्जी कॉलेज खोल दिये और चिकित्सा के नाम पर **'आयुष्मान भारत'** का झुनझुना जनता को थमा दिया। इस सबके बावजूद गूजर महोदय अपनी पीठ थपथपाने में कतई कोई शर्म महसूस नहीं करते।

उद्योगपतियों की इस बैठक में विपुल गोयल

उद्योगपतियों की सभा उद्योग मंत्री के बिना तो संभव ही नहीं और वह भी तब जब वह स्थानीय विधायक हो। लिहाजा केन्द्रीय मंत्री से 36 का आंकड़ा होने के बावजूद उद्योग मंत्री इसमें मौजूद रहे। दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे को बड़ा-छोटा भाई कह कर सम्बोधित किया, परन्तु दिल तो दूर, नज़रें तक भी मिलती नज़र नहीं आई।

सैंकड़ों करोड़ का राजस्व देने वाले इन उद्योगों तक पहुंचने के लिये न तो पर्याप्त ढंग की सड़कें हैं न ही बिजली, पानी व सीवर की उचित व्यवस्था। चार साल तक सत्ता-सुख भोग चुकी भाजपा के उद्योग मंत्री ने अब आखरी वर्ष में इन समस्याओं के समाधान हेतु 170 करोड़ खर्च करने का आश्वासन तो जरूर दिया, परन्तु देखने वाली बात यह होगी कि इस रकम का कितना भाग कामों पर लगेगा और कितना भाग रिश्वतखोरी व कमीशनखोरी की भेंट चढेगा।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 1 डी/2बी.पी. नियर हार्डवेयर चौक, एनआईटी फरीदाबाद से प्रकाशित किया। Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06